JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका"

पर्यवेक्षिका
डॉ0 मंजु झा
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा

शोध छात्रा
कंचन कुमारी
समाजशास्त्र विभाग
ल0 ना0 मि0 विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा
मोबाईल नम्बर– 7564033525
Email ID- Kanchanphd2019 @gamil.com

प्रस्तावना :

''जल है तो कल है''। हर व्यक्ति को जल संरक्षण के महत्त्व की ओर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के लिए जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुंओं, नलकूपों अथवा हैण्डपम्पों से प्राप्त करता है। देश दुनिया में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की खपत अत्यधिक मात्रा में हो रही है जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है।

भारत में कई शहर तथा गाँव पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। राज्य ने तकनीकी आधारित समाधानों में निवेश किया है ताकि पानी की समस्या समाप्त हो सकें और आसानी से स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकें। विभिन्न गांवों तथा शहरों में योजना तथा सम्मेलन द्वारा जल की आपूर्ति प्रक्रिया, पानी की गुणवत्ता पेयजल स्त्रोतों, घरेलू नल कनेक्शनें, जल संसाधनों तथा जल संरक्षण के बारे में विशेष तकनीकी जानकारी दी जा रही है तथा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए सरकार जल प्रबंधन के एकजुट प्रयास से कुंओं, जल निकायों, तालाबों और पारम्परिक जल स्रोतों का भी निर्माण किया है।

जल संरक्षण :

प्राकृतिक में जल उपलब्धता में गिरावट को रोकने तथा जल को बचाने की प्रक्रिया एवं विधि को जल संरक्षण कहा जाता है।

जल संरक्षण का मूल तात्पर्य होता है जल का बचाव करना एवं जल प्रबन्धन करना। इस क्रम में **श्री सरावगी** जल संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी के महत्वकांक्षी ''जल जीवन हरियाली अभियान'' में जब तक आम लोगों की सहभागिता नहीं होगी तब तक यह सफल नहीं होगा। इस आधार पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति जल संरक्षण की दिशा में काम करना चाहते है तो जिला प्रशासन इसकी निःशुल्क व्यवस्था करेगा। इस काम के लिए जिलें में 24 जेई, एक सहायक अभियंता और एक कार्यपालक अभियंता काम कर रहे है।

मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी ने जलवायु परिवर्तन की दशा को देखते हुए वर्ष 2019 से ही जल संरक्षण और पर्यावरण पर अनेकों कार्य कर रहे है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले तीन साल में ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' का लक्ष्य पूरा करने के लिए 24,500 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इसके तहत राज्य के एक लाख तालाब, आहर एवं पइन को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और तालाबों की उड़ाही की जायेगी। तीन लाख कुंओं को अतिक्रमण मुक्त कर जीर्णोद्धार कराया जाएगा। जल संरक्षण के लिए कुंओं और चापाकल के पास सोख्ता का निर्माण तथा वर्षा जल संचय की योजनाओं पर कार्य होगा। क्योंकि जल एवं हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित हैं।

बिहार राज्य के पटना जिला के सरकारी स्कूलों में जल संचय की पाठशाला के दौरान शिक्षकों द्वारा जल संरक्षण के महत्व की चर्चा की गई। देशभर में पानी के अभाव वाले जिलों में ''**जल संरक्षण अभियान**'' चलाया गया। इस अभियान के तहत बिहार के सभी स्कूलों में बच्चों को जल की महत्ता एवं संरक्षण पर जागरूक करने के लिए विशेष बल दिया गया। राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जल संरक्षण तथा जल संचयन प्रणाली (रेन वाटर हार्वेस्टर) के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रमुख चार विषयों को केन्द्रित किया गया– जल चक्र, जलसंरक्षण के तरीकें (सोख्ता, वर्षा जल, संचयन आदि) पानी स्वस्थ जीवन का आधार, जल स्रोत एवं तरल अपशिष्ट जल का प्रबंधन।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि जल संरक्षण एक विकराल समस्या है जो सम्पूर्ण मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौति बनकर खड़ी है। जल सामान्य रूप से मानव अस्तित्व और

सभ्यता के प्रमुख कारणों में से एक है, जिसे संरक्षित करके रखना हर एक मानव जाति का कर्तव्य है। जल की समस्या पूरे विश्व में काफी विस्तृत रूप में फैली हुई है जिसके कारण नदियाँ तालाब तथा कुंआ इत्यादि सूख रहा है और पानी का स्तर काफी नीचे की ओर जा रहा है। जिससे पानी की समस्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रत्येक गाँव, शहर, नगर आदि जल की समस्या से ग्रसित हो रहे है, कारणवस उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका एकमात्र उपाय है जल का संरक्षण।

जल संरक्षण का महत्व :

जल प्रकृति की अमूल्य देन है। जीवित रहने के लिए जल अतिआवश्यक है। जल प्रत्येक व्यक्ति, जीव–जन्तु तथा पेड़–पौधे आदि सभी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है । इस क्रम में राज्य सरकार ''जल संरक्षण अभियान'' चला रही है। जल बचत तकनीकी लोगों को बताई जा रही है। इस सिलसिले में प्रदूषण से बचाव तथा लुप्त एवं अतिक्रमित पारंपरिक जल निकायों की पहचान की जा रही है।

राज्य सरकार बिहार के जल निकायों के मानचित्र का एटलस तैयार करेगी। इस एटलस में गाँव स्तर पर राज्य की 100 से अधिक नदियों तथा 40 हजार से अधिक तालाबों को मानचित्र के माध्यम से दिखाया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने **''जल जीवन हरियाली''** के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में उपलब्ध सतही जल संसाधनों के प्रबन्धन में सार्वजनिक व निजी तालाबों की अलग–अलग पहचान की जायेगी।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है ''जल ही जीवन है''। जल के महत्व को बताते हुए **''संयुक्त राष्ट्र संघ''** ने वैश्विक जल रिपोर्ट 2006 में कहा था कि ''हमारे धरती पर हर किसी के लिए पर्याप्त पानी है, किन्तु फिर भी जल संकट बरकरार है।'' इसका प्रमुख कारण कुप्रबन्धन भ्रष्टाचार, उचित संसाधनों की कमी और भौतिक बुनियादी ढ़ांचे में निवेश की कमी है।

जल संरक्षण की आवश्यकता :

भारत में जल संकट का मूल कारण पानी की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि पानी की बर्बादी और कुप्रबन्धन है। मानसून और जलवायु परिवर्तन ने जल संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में बेहतर जल प्रबंधन से ही इन हालातों से निपटा जा सकता है।

श्रवण कुमार ने कहा कि स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण के लिए पृथ्वी पर 33 प्रतिशत हरियाली की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार नें **''जल शक्ति मंत्रालय''** का गठन कर **''जल शक्ति**

अभियान'' की शुरूआत की है। देश में 36 राज्यों के 256 जिलों के 1592 प्रखण्डों में जल शक्ति अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें बिहार के 12 जिलें के 30 प्रखण्डों का चयन किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के विकास के साथ–साथ देश में संसाधनों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जिसमें देश के कई भागों में पानी की समस्या काफी देखने को मिल रही है। इसलिए भारत के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

जल संरक्षण की समस्या :

प्राकृतिक जल संसाधनों के स्रोत दिन–प्रतिदिन नष्ट होते चले जा रहे है। लेकिन आज के समय में मनुष्य के सामने जल संरक्षण की समस्या काफी विस्तृत रूप में फैलते जा रहा है। इस क्रम में **''तालाब बचाओं अभियान'' के प्रवर्तक नारायण जी चौधरी** ने कहा कि दरभंगा शहर के लोग अपने सुखी जीवन को परेशान करने के लिए अपना कब्र स्वयं खोदना शुरू कर चुके है। लोगों ने बड़े–बड़े नालों को भरकर उस पर मकान बना लिया है। भूमाफियाओं ने शहर के विभिन्न प्रमुख तालाबों को भरकर उस पर इमारतें खड़ी कर दी है। इससे जल जमाव की समस्या और जल के बहाव की समस्या दोनों ही समस्याएं उत्पन्न हो गई है।

इस प्रकर जल की समस्या हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी विडम्बना है। जिसका असर सम्पूर्ण मानव जाति पर पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण है–वर्षा की कमी, शुद्ध पेयजल का अभाव, जल का दुरूपयोग, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जल प्रदूषण और सूखाग्रस्त क्षेत्र इत्यादि।

जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका :

धरातल पर बहने वाली जल की धारा नदी कहलाती है और नदियों की धारा की हमारे दैनिक जीवन से लेकर सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में भी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है अतः इसका संरक्षण जरूरी है।

कहा जाता है कि ''जल ही जीवन है'' और जीवन देने की शक्ति ईश्वर ने महिलाओं को प्रदान की है। क्योंकि इतिहास में अधिकत्तर सभ्यताओं ने जल तथा महिलाओं को जीवन का स्रोत माना है। जल संरक्षण के प्रयोग के प्रति नए दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, जो तकनीकी ज्ञान पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों पर भी आधारित होगा। जल के लिए महिलाओं एवं महिलाओं के लिए जल की महत्ता को डबलिन सम्मेलन में औपचारिक मान्यता दी गई थी।

डबलिन घोषणापत्र में जल की प्रभावी एवं पर्याप्त उपलब्धता के जो सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये थे उनमें से एक पेयजल तथा स्वच्छता के लिए सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी रही है।

रियों में 1992 में सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में पानी की रोजमर्रा की आपूर्ति रख–रखाव तथा इस्तेमाल में महिलाओं की अहम भूमिका देखते हुए यह तथ्य तो स्वीकार किया गया कि जल प्रबन्धन के सभी चरणों में महिलाओं की सहभागिता से जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना को लाभ मिल सकता है, लेकिन जल प्रबन्धन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की जरूरत है।

जल संरक्षण एवं प्रबन्धन में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से जल संरक्षण की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। 14 मार्च को नदियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कारवाई दिवस के रूप में मानाया गया। जिसकी थीम भी महिला, जल और जलवायु परिवर्तन पर केन्द्रित है। जिसमें महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। घर परिवार में तथा सिंचित अथवा वर्षा सिंचित फसलों की किसान के रूप में पानी इक्ठा करने, इस्तेमाल करने और उनके प्रबन्धन में उनकी महत्वपूर्ण सहभागिता के कारण महिलाएँ जल संरक्षण की कड़ी और उनके पास जल संरक्षण एवं संसाधन की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता सीमा और भंडारण के उचित तरीकों समेत पीढ़ीयों से मिला ज्ञान है। साथ ही साथ महिलाओं के कारण जल संसाधन विकास एवं सिंचाई की नीतियों तथा कार्यक्रमों को पूरा करने की कुंजी भी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि पानी की कमी से देश के कई हिस्से साल–भर प्रभावित रहते है। बारिश से जो भी पानी हमें मिलता है, अभी उसका 8% ही बचाया जाता है। जनशक्ति से इसका समाधान किया जा सकता है। जल महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए नया ''जल शक्ति मंत्रालय'' बनाया गया है। इस क्रम में मोदी जी ने कहा कि पंजाब में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए नालों को ठीक किया जा रहा है। तेलंगाना के थिमाई पिल्ली में टैंक के निर्माण से गाँव की जिंदगी बदल रही है। राजस्थान के कबीर धाम में खेतों में बनाए गए छोटे तालाबों से एक बड़ा बदलाव आया है। तमिलनाडु के वेल्लोर में सामूहिक प्रयास से नागनदी को पुनर्जीवित करने के लिए 20 हजार महिलाएँ आगे आई है।

मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी ने कहा कि 'जल–जीवन–हरियाली अभियान' से जीविका समूह की दीदियाँ जुड़ेगी। उन्होंने कहा कि धीरे–धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे पर्यावरण संकट की स्थिति बन रही है। प्रदूषण भी बढ़ रहा है। मानसून का समय पहले से अनियमित हो गया है। इस संकट

से उबरने के लिए जीविका समूह की दीदियाँ द्वारा जिल में चयनित 156 पंचायतों में 20 हजार 66 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रशिक्षित अर्थशास्त्री मैदा बिलाल एको विस्ट्रों नागरिक संघ की सह–संस्थापक व अध्यक्ष जिन्होंने 2017 के अन्त में बोस्निया की क्रुसिका नदी जो 150,000 लोगों के लिए मुख्य जल स्रोत है। अगस्त 2017 में 40 वर्षीय मैदा बिलाल ने इसी का विरोध शुरू किया। इन्होंने अपने गाँव की 300 महिलाओं और पुरूष संग नदी पर प्रस्तावित लघु संयत्र को नहीं बनने देने के लिए बिलाल ने 500 दिनों तक पहरा दिया। मैदा को इस संघर्ष में मध्य बोस्निया में दिसम्बर 2018 में सफलता मिली। 15 जून को पुरस्कार वितरण समारोह में मैदा के कामों को सराहा और बोस्निया की महिला मैदा बिलाल को वर्ष 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हमें महिलाओं के सक्रिय सहभाग के साथ जल संरक्षण प्रबन्धन में उनकी दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः आज के वर्तमान समय में विश्व, राष्ट्र, राज्य व गाँव स्तर पर महिलाएं भी जल संरक्षण में भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हमें गंगा नदी को लेकर उमा भारती का कार्य, नर्मदा नदी को लेकर मेद्या पाटकर का नाम मिलता है तथा महाराष्ट्र में उल्ला महाजन का कार्य उल्लेखनीय है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कराए गए जल संरक्षण के सरकारी प्रयास :

देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कई वर्षों तथा हाल के वर्षों में जल की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के सरकार द्वारा जल संरक्षण की योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जो प्रमुख महत्वपूर्ण व निम्नलिखित है :–

1. **हर–घर–नल–जल योजना :**

   सितम्बर 2016 में मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी ने ''हर घर नल जल'' का कार्य कर देश को नजीर बनाया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 1 लाख 14 हजार 733 वार्डों में से 58 हजार 654 में पंचायती राज और 56 हजार 79 वार्डों में लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मार्च 2020 तक सभी घरों में नल से जल की आपूर्ति कर देनी है।

2. जल जीवन हरियाली अभियान :

बिहार राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को **''जल–जीवन–हरियाली अभियान''** के लिए जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस क्रम में मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी ने कहा कि अगले तीन साल में जल–जीवन–हरियाली अभियान का लक्ष्य पूरा करने के लिए 24,500 करोड़ रूपये खर्च होगें।

3. सिंधु जल संधि :

वर्ष 1960 में भारत के तत्कालिन **प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू** और **पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान** के बीच हुई थी यह ''सिन्धु जल संधि''। इस संधि के मुताबिक भारत पूर्वी नदियों, मसलन, सतलज, रावी और व्यास का पानी इस्तेमाल करेगा, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी नदियों, मसलन–सिन्धु, झेलम तथा चिनाव का पानी इस्तेमाल करेगा।

4. जल–जीवन मिशन योजना (शहरी) :

15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी** ने घोषणा की। जिसके तहत 2021–22 के केन्द्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य–6 (SDG-6) के अन्तर्गत शहरों के सभी घरों में नल के माध्यम से वर्ष 2026 तक जल का कनेक्शन पहुँचने के लिए 'जल जीवन मिशन–शहरी' की शुरूआत की गई। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 2,87,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप लाइन के जरिये जलापूर्ति करना है।

5. कोशी–मेची नदी जोड़ योजना :

कोसी–मेची नदी जोड़ योजना में कोसी बेसिन के पानी को महानंदा बेसिन में लाया जाएगा। दोनों नदियों के पानी को मिलाने के लिए लगभग 120 किमी लंबे कैनाल का निर्माण होगा। यह नहर मुख्यतः नेपाल के तराई क्षेत्र से गुजरेगी। साथ ही बकरा, रावता और कंकई तीन छोटी–छोटी नदियों को भी जोड़ेगी। कोसी का पानी अभी खगड़िया के कुरसेला में मिलता है। योजना में कोशी के पानी को अररिया में महानंदा में गिराया जाएगा। मौजूदा आकलन के अनुसार इस योजना में लगभग 5500 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

6. **हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना :**

'हिमालय प्रदेश पर्वत धारा योजना' की घोषणा **मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी** के द्वारा की गई तथा इसका आरंभ हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा किया गया। इस योजना का संचालन धरती पर पानी का ठहराव रोकने एवं जल स्तर में वृद्धि करने हेतु किया गया। जिससे राज्य में भूजल स्तर में वृद्धि तथा लोगों को सिंचाई करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी।

7. **सुजलाम् सुफलाम जल संरक्षण अभियान :**

गुजारात के 58 वें स्थापना दिवस के शुभअवसर पर **मुख्यमंत्री विजय रूपाणी** ने 'गुजरात सुजलाम् सुफलाम जल संरक्षण अभियान 2020' की शुरूआत की। इस अभियान के तहत पारम्परिक जल संसाधनों को संरक्षित करना और लगभग 13,000 तालाबों को गहरा करना एवं बांधों की जाँच करने का लक्ष्य रखा गया है।

निष्कर्ष :–

जल संरक्षण की समस्या आज 21 वीं सदी में पूरे विश्व में काफी विस्तृत रूप में फैली हुई है। जिससे समाज को, सामाजिक प्राणियों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्रम में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाये गये योजनाओं के कार्यों के जरिये उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की गई, जो जल से जुड़ी से समस्या है। जैसे– पीने के लिए पेयजल की आवश्यकता, कृषि के लिए सिंचाई जल की आवश्यकता, बारिश के बूंदों का संरक्षण, जल के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, जल के स्रोत कुंआ, तालाब, पोखर, नदियां एवं चापाकल इत्यादि का संरक्षण करना जिससे आनेवाले समय में जल की समस्या कम हो और इस कुप्रभाव से बचा जाए।

संदर्भ :–

1. हिन्दुस्तान टीम (2021) : जल संरक्षण की समूह महिलाओं ने लिया संकल्प, बरेली पब्लिकेशन।
2. हिन्दुस्तान (2021) : जल और पर्यावरण संरक्षण से बदलेगा बिहार : सी.एम।
3. हिन्दुस्तान (2019) : राज्य के सरकारी स्कूलों में लगेगी जल संचय की पाठशाला।
4. हिन्दुस्तान (2019) : जल संरक्षण के लिए डी.एम करेंगे सम्मानित।
5. हिन्दुस्तान (2019) : जल जीवन हरियाली पर 24 हजार 524 करोड़ खर्च

होंगें।

6. हिन्दुस्तान (2021) : नालों को भरकर बना रहे घर, होगी परेशानी : चौधरी।
7. हिन्दुस्तान (2019) : नल जल योजना देश भर में लागू होगी।
8. हिन्दुस्तान (2019) : बिहार के जल निकायों का बनाया जाएगा एटलस।
9. हिन्दुस्तान (2019) : राज्य के 3 लाख कुंओं से अतिक्रमण हटाएँ जाएगें।
10. हिन्दुस्तान (2022) : कोसी–मेची नदी जोड़ राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो : संजय।
11. परवीन डॉ0 नाज : जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका हिन्दुस्तान समाचार।